जनसत्ता

हिंसा का दायरा

देश के अलग-अलग हिस्सों में वहां के स्थायी निवासियों और कथित बाहरी लोगों के बीच हितों के टकराव के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। कई बार अवसरों और अधिकारों के सवाल पर दो पक्षों के बीच हिंसक हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसे चिंताजनक मौके अनेक बार आने के बावजूद इस दिशा में न तो राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया जाहिर करने में सावधानी बरतना जरूरी लग रहा है और न सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले मामले की संवेदनशीलता समझने की जरूरत लग रही है। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में छह गैर अरुणाचली जनजातियों को पीआरसी यानी स्थायी आवास प्रमाणपत्र देने के मसले पर पिछले कई दिनों से हिंसक माहौल बना हुआ है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि बेलगाम और अराजक हो चुके लोगों ने वहां के उप-मुख्यमंत्री चाउना मीन के आवास पर हमला कर दिया और वहां आगजनी भी की। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ समूहों को अगर सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने का मौका मिल रहा है तो इसकी वजह सरकार की अदूरदर्शिता ही है कि उसने पीआरसी के मुद्दे के महत्त्व पर समय रहते विचार नहीं किया। अगर इस मुद्दे पर समय रहते जमीनी स्तर पर राज्य के नागरिकों और संगठनों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई होती, तो आज सरकार के सामने यह नौबत नहीं आती।

गौरतलब है कि 1987 में असम से अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद से अरुणाचल प्रदेश के नामसाइ और छांगलांग में पिछले कई दशक से छह जनजातियों के करीब पच्चीस हजार लोग भी रह रहे हैं। लेकिन उनके पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है। इसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर पिछले साल मई में एक संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी, जिसे यह तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य में बसने वाली छह गैर-अरुणाचली जनजातियों को वहां पीआरसी दिया जाए या नहीं। समिति ने गैर-अरुणाचली समुदायों को भी राज्य में पीआरसी देने की सिफारिश की थी। लेकिन उसके बाद राज्य में कई छात्र संगठनों सहित स्थानीय जनजातीय समूहों की ओर से तीखा और हिंसक विरोध खड़ा हो गया। विरोध जताने वाले लोगों और संगठनों का कहना है कि जिन समुदायों को पीआरसी मुहैया कराने की बात हो रही है, उससे स्थानीय आदिवासी समूहों के रोजगार और दूसरे अधिकारों या हितों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

ऐसा लगता है कि शुरुआती तौर पर शायद सरकार इस विरोध के असर को कम करके आंक रही थी, जिसकी वजह से राज्य में हिंसा का दायरा फैल गया। अब सरकार ने पीआरसी पर अगला कदम उठाने से इनकार किया है, ताकि सबसे पहले हिंसा पर काबू पाया जा सके। सवाल है कि क्या सरकार को गैर-अरुणाचली जनजातीय समुदायों के मसले के हल के लिए किसी नीतिगत फैसले की घोषणा के असर का अंदाजा नहीं था? जिन जनजातियों को पीआरसी देने के सवाल पर ताजा विवाद शुरू हुआ, क्या उस पर स्थानीय समुदायों को तर्कपूर्ण तरीके से समझाने और उन्हें विश्वास में लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था? हिंसा के भयानक रूप लेने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नागरिकता संशोधन विधेयक का भी समर्थन किया था। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर व्यापक असंतोष सामने आ रहा है। ऐसे में अगर आंतरिक मुद्दों को निपटाने और उसका सर्वमान्य हल निकालने में लापरवाही बरती जाती है तो स्थिति ज्यादा जटिल हो सकती है।

राहत का फैसला

घर खरीदने वालों को जीएसटी परिषद ने जो कर राहत दी है, वह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसका पहला फायदा तो यही होगा कि लंबे समय से ठप पड़े रियल एस्टेट बाजार में फिर से जान आएगी और लोगों को वाजिब दामों पर मकान मिल सकेंगे। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा झटका रियल एस्टेट बाजार को ही लगा था और मकानों की खरीद में बड़े पैमाने पर होने वाले नगदी के चलन पर अंकुश लगा था। इसका पहला असर यह देखने को मिला कि लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार में बनी कृत्रिम तेजी खत्म हो गई और मकानों के दाम तेजी से गिरने लगे। तब से इस क्षेत्र में मंदी जैसी हालत चल रही है। लेकिन अब खरीदारों को राहत मिलने से रियल एस्टेट बाजार तो उठेगा ही, सीमेंट, इस्पात जैसे क्षेत्रों में भी मांग निकलेगी, मकान के लिए बैंक कर्ज लेने वालों की भी मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को इससे बल मिल सकता है।

जब से जीएसटी लागू किया गया है तब से इसकी कर-दरों को आसान बनाने पर लगातार काम चल रहा है। कुछ महीने पहले कर की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए ज्यादातर वस्तुओं को कम दर वाली श्रेणी में लाया गया था, लेकिन रियल एस्टेट क्षेत्र लंबे समय से ऐसी राहत की प्रतीक्षा कर रहा था। जीएसटी परिषद ने दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी महानगरों में साठ वर्ग मीटर और छोटे शहरों में नब्बे वर्गमीटर कारपेट एरिया और पैंतालीस लाख रुपए तक की कीमत वाले ऐसे फ्लैटों पर जो निर्माणाधीन हैं, जीएसटी की दर घटा कर अब एक फीसद कर दी है। पहले यह आठ फीसद थी। अगर फ्लैट का क्षेत्रफल इससे ज्यादा होगा या कीमत ज्यादा होगी तो जीएसटी पांच फीसद लगेगा, जो अभी तक बारह फीसद देना पड़ता है। जाहिर है, खरीदारों के लिए यह बड़ी राहत है। इसका सीधा असर यह होगा कि सामान्य वर्ग के खरीदारों को घर अब दो से तीन लाख रुपए सस्ता पड़ेगा। जो लोग बीस से तीस लाख रुपए (किफायती वर्ग में) के बीच मकान खरीदना चाहेंगे उन्हें डेढ़ से दो लाख तक की बचत होगी। इसके अलावा खरीदार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो लाख साठ हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान ब्याज के रूप में मिलेगा। इस रियायत का सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग को मिलेगा।

काम-धंधे की तलाश में छोटे शहरों और गांवों से लोग जिस तेजी से महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उससे बड़े शहरों में मकानों की मांग बढ़ी है। बड़े शहर में घर सबका सपना होता है। लेकिन अभी तक खरीदारों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि मकान काफी महंगे थे। ज्यादातर बिल्डर तो नियम-कानूनों को मानते भी नहीं थे और मनमाने दामों पर ही मकान बेचते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिल्डरों पर शिकंजा कसा है और मनमानी कम हुई है। जीएसटी परिषद का यह फैसला अच्छा तो है, लेकिन बेहतर होता कि इसे तत्काल लागू किया जाता। ये दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। नई दरों को तत्काल लागू करना खरीदारों और बिल्डरों दोनों के लिए ही लाभकारी होता। हालांकि बिल्डरों को इस फैसले से थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, क्योंकि सीमेंट अभी भी जीएसटी की अट्ठाईस फीसद वाली कर-श्रेणी में ही है। इसके अलावा बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ परिषद ने नहीं दिया है। इससे कहीं न कहीं बिल्डरों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद जीएसटी परिषद का यह कदम लोगों के घर के सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।

कल्पमेधा

युद्ध मानवता को ग्रसित करने वाला सबसे बड़ा प्लेग है। यह धर्म को नष्ट करता है, परिवारों को नष्ट करता है। कोई भी महामारी इससे बेहतर है।
-मार्टिन लूथर किंग

आतंकवाद और दोहरा रुख

राहुल लाल

पुलवामा हमले की चीन ने निंदा की है, लेकिन मौलाना मसूद अजहर को लेकर कोई ठोस बात नहीं की है। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को दो बार वीटो कर दिया। हालांकि 2017 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन ने जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी संगठन करार दिया था, फिर भी संयुक्त राष्ट्र में वीटो के द्वारा मसूद अजहर का बचाव जारी है। इसका प्रमुख कारण है चीन और पाकिस्तान की घनिष्ठ मित्रता।

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देशभर में आतंकवाद को लेकर आक्रोश उच्चतम स्तर पर व्याप्त है। पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर भारत ने उससे आर्थिक क्षेत्र के विशिष्ट तमगे 'सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र' (एमएफएन) का दर्जा भी वापस ले लिया है। पाकिस्तान से आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क में भी दो सौ फीसद की वृद्धि कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालत यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार नौ अरब डॉलर रह गया है, जबकि बांग्लादेश का तैंतीस अरब डॉलर है। लेकिन ऐसे में जब पाकिस्तान को संपूर्ण दुनिया में आतंकवाद के पोषण स्थल के रूप में माना जा रहा है, फिर भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बीस अरब डॉलर का समझौता किया, जिसमें ग्वादर बंदरगाह के नजदीक एक तेल रिफाइनरी में आठ अरब डॉलर का निवेश भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि सऊदी अरब जिसके भारत से काफी अच्छे संबंध हैं, वह भारत के समर्थन में पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बना रहा?

इस सवाल के जवाब के लिए मध्यपूर्व के संवेदनशील क्षेत्र में शिया और सुन्नी विवाद को समझना होगा। सऊदी अरब संपूर्ण दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की अगुआ और धर्मगुरु होने का दावा करता है, जबकि ऐसा ही दावा ईरान शिया समुदाय को लेकर करता है। पाकिस्तान भी सुन्नी बहुल मुसलिम देश है जो ईरान के विरुद्ध सऊदी अरब को सदैव सुरक्षा सहयोग देने का आश्वासन देता है और आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखता है। यही कारण है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में परमाणु क्षेत्र में भी पहले से निवेश कर रखा है। जमाल खशोगी हत्याकांड के बाद पिछले कुछ महीनों में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की छवि खराब हुई है। ऐसे में सलमान पाकिस्तान जैसे परंपरागत मित्रों को अपने साथ कर पुनः मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं। सऊदी के पैसे से इस्लामिक कट्टरता में भी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वह भी अंततः आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है। स्पष्ट है कि निजी हितों के लिए आतंकवाद को माध्यम बनाया जा रहा है।

सऊदी अरब की तरह चीन का भी आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया रहा है। पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। जैश के प्रमुख मसूद अजहर को चीन वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से बचाता रहा है। पुलवामा हमले की चीन ने निंदा की है, लेकिन मौलाना मसूद अजहर को लेकर कोई ठोस बात नहीं की है। चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने वाले प्रस्ताव को दो बार वीटो कर दिया। हालांकि 2017 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन ने जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी संगठन करार दिया था, फिर भी संयुक्त राष्ट्र में वीटो के द्वारा मसूद अजहर का बचाव जारी है। इसका प्रमुख कारण है चीन और पाकिस्तान की घनिष्ठ मित्रता। पाकिस्तान की संपूर्ण दशा-दिशा वहां की लोकतांत्रिक सरकार नहीं, बल्कि सेना एवं कट्टर चरमपंथी संगठन मिल कर तय करते हैं। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है। अमेरिका से पाकिस्तान की दूरी बढ़ने पर पाकिस्तान एक तरह से चीन का उपनिवेश ही बन गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान पर चीन का दबदबा बढ़ गया है। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय विदेश नीति को चीन के प्रति भी आक्रामक बनाया जाए।

न्यूयार्क में विश्व व्यापार केंद्र और वाशिंगटन में पेंटागन पर 2001 के हमले के बाद अमेरिका नाटो सेनाओं के साथ विश्वभर में हस्तक्षेप करता रहा है। लेकिन देखा जाए तो यह आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कम और वर्चस्व तथा संसाधनों की लूट की लड़ाई ज्यादा थी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि वहां खतरनाक रासायनिक हथियार हैं। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई, लेकिन अमेरिका इराक में आज तक रासायनिक हथियारों को तो ढूंढ़ नहीं पाया। इराक को हमेशा के लिए राजनीतिक एवं संघर्षात्मक हिंसा के लिए छोड़ दिया, जो आगे चल कर इस्लामिक स्टेट (आइएसआइएस) का क्षेत्र बन गया था। इस मामले से पश्चिम की आतंक के विरुद्ध आधी-अधूरी लड़ाई को समझा जा सकता है।

अमेरिका के लिए मध्यपूर्व ऊर्जा संसाधनों और

भू-राजनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूरोप तथा एशिया को जोड़ता है। रूस ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और दोनों महाशक्तियों के बीच जोर आजमाईश प्रारंभ हो गई। अगर सीरिया मामले को ही देखें तो आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस दो ध्रुवों पर खड़े हैं। रूस जहां बशर अल असद को समर्थन दे रहा है, वहीं अमेरिका विद्रोहियों को। रूस ने असद विद्रोहियों पर कार्रवाई की तो विरोध में अमेरिका ने असद को कमजोर करने के लिए सीरिया पर बड़ा रासायनिक हमला कर डाला। इस तरह से तो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष संभव नहीं हो सकता। सीरिया की अधिकांश जनता सुन्नी है, वहीं बशर शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय प्रभुत्व और सुन्नी वर्चस्व स्थापित करने के लिए सऊदी अरब भी अमेरिकी समूह में शामिल हो गया। वहीं बशर के शिया होने के कारण ईरान के हिजबुल्लाह लड़ाके भी बशर के समर्थन में आए। इस तरह शिया-सुन्नी विवाद के कारण कई बार आइएस को सीरिया में सऊदी अरब और अमेरिका में संरक्षण भी मिल जाता था। जाहिर है, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर अमेरिका की यह दोहरी और स्वाथपूर्ण नीति है। अमेरिका और ब्रिटेन ने नाटो सेनाओं के साथ मिल कर मध्यपूर्व और अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के बजाय इनके राष्ट्रीय हित प्राथमिक में रहे। पहले जब भारत आतंकवाद के खिलाफ बात करता था तो विकसित माने जाने वाले अधिकांश देश इसे तवज्जो ही नहीं देते थे। लेकिन जब आतंकियों ने पश्चिमी देशों में पांव पसारे तो अमेरिका के साथ यूरोप की भी आंखें खुलीं।

आतंक के खिलाफ पश्चिमी देशों के युद्ध के साथ ही कारोबार, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद के दौर की भी शुरुआत हो गई है। आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि विश्व समुदाय आतंकवाद पर दोहरा रवैया रखना बंद करे। आइएसआइएस जैसे आतंकवादी संगठनों के प्रति भी पश्चिमी देशों का शुरुआती रवैया गंभीर नहीं था। कुछ खुफिया एजेंसियों का तो यह भी दावा था कि पश्चिमी राष्ट्र आइएस को प्रोत्साहन देकर दस डॉलर प्रति बैरल से भी सस्ता तेल खरीद कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहे थे। जब यह संगठन उन देशों के लिए भी संकट बनने लगा तब जाकर पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण और भूमिका बदली। वर्ष 2017 में सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में इस दशक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें चार सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भले ही सभी आतंकवादी घटनाओं को एक रूप में देखने की शपथ ली जाती है, परंतु व्यवहार में ऐसा नजर नहीं आता। महाशक्तियों को समझना होगा कि भेदभावपूर्ण नीतियों से आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कमजोर होता है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष संपूर्ण विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है। अब महाशक्तियों व क्षेत्रीय शक्तियों को आतंकवाद के नाम पर शक्ति संघर्ष के स्थान पर एकीकृत सोच अपनानी होगी। आतंकवाद पूरे विश्व में कहीं भी हो, यह मानवता के ऊपर बड़ा धब्बा है। विश्व समुदाय को चाहे आतंकवादी संगठन हों या पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को खुलकर प्रायोजित करते हैं, उनसे कठोरता से निपटना होगा, तभी आतंक के खिलाफ संघर्ष के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

आपका परिचय

अंबालिका

दुनिया मेरे आगे

हाल ही में एक मित्र के साथ थी तो उनके सहयोगी ने औपचारिकता का निर्वाह करते हुए मेरी ओर रुख करके पूछा- 'आपका परिचय?' मैं स्वभाव से संकोची हूं। अचानक इस प्रश्न से थोड़ा हिचकिचा गई। हालांकि यह एक सामान्य औपचारिकता है, लेकिन मुझे यह प्रश्न बहुत विचित्र लगता है। 'परिचय' पूछे जाने के बाद हम भले ही अपना नाम और साथ में काम बता दें, लेकिन आज भी मैं इस शब्द को परिभाषित करने में सहज नहीं हो पाती हूं। असमंजस की स्थिति बन जाती है। यों सामान्य तौर पर देखें तो इस प्रश्न में कुछ भी विशेष नहीं है। व्यावहारिक पक्ष यही कहता है कि प्रश्न अति साधारण है- परिचय! मगर मेरा मन-मस्तिष्क इस परिचय की सीमा को मापने में इतना निर्बल हो जाता है कि इस शब्द से भागना चाहता है। मैं 'परिचय' में क्या निहित मानूं? कुछ वर्णमालाओं का सार्थक व्यवस्थित संयोजन, जिसे मैं अपना 'शुभ' नाम कहती हूं, क्या केवल वही मेरा परिचय है? या किसी कार्यस्थल का कोई पदभार संभालती अपने पद से अवगत कराऊं। इससे कुछ आगे बढ़ूं तो जिसके साथ किसी जगह पर मौजूद हूं, उसके साथ अपने संबंध का उल्लेख करूं? विवाहित हूं तो निस्संदेह अपने पति के नाम को अपना 'परिचय-पट्ट' मानूं! कहां है परिचय की सीमा?

क्या मेरा ज्ञान और मेरी सोच-समझ मेरे परिचय में शामिल है? या फिर इन सबसे अलग मैं अपने साथ किसी जाति और संप्रदाय की भी प्रतीक हूं? हमारे जन्म के साथ ही समाज का सबसे विवादित रूप हमसे जुड़ जाता है- धर्म। धर्म हम तय नहीं करते। मां के गर्भ में ही इसका निर्धारण हो जाता है कि हम समाज के किस तबके में आएंगे और हमारे परिचय का आवरण किस जाति और धर्म से आवृत्त होगा। इससे तैयार होने वाला विभाजन एक ऐसी विडंबना है, जिसका तोड़ मिल भी जाए तो उसे लागू करना मुश्किल लगता है। समाज में ऊंची कही जाने वाली जातियों के लोग आज भी सिर उठा कर चलते दिखते हैं और निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों को परिचय तक के लायक नहीं समझते। एक क्षत्रिय के लिए उसका विशेष परिचय उसका क्षत्रिय होना है। उसकी शान में कोई खलल नहीं आना चाहिए। दूसरी ओर एक ब्राह्मण सिर्फ अपने जन्म की वजह से खुद को समाज में सबसे उच्च समझता है। लेकिन मानव होने के नजरिए से सोचें तो क्या यह उचित है?

क्या परिचय इतनी तुच्छ वस्तु है, जिसे धर्म और जाति विशेष से जोड़ कर समेट दिया जाए? मैं नहीं मानती आदिकाल से चली आ रही वर्ण व्यवस्था केवल समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का पर्याय रही होगी। जब तकनीक उन्नत नहीं थी, जब व्यक्ति के पास अतिशय समय था, तब वह उन कार्यों को करता था जो उसके सामर्थ्य के दायरे में था। लेकिन सुविधा और सत्ता के लोभ में समाज के समर्थ तबकों ने पहले लोगों को श्रेणियों में बांट दिया, फिर सामाजिक सत्ता पर खुद काबिज हो गए और धारणाओं से लेकर व्यवहार तक को संचालित करने लगे। मानवता के हनन की शुरुआत शायद वहीं से हुई होगी।

आज जब हम संचार युग में जी रहे हैं तो इस तरह की रूढ़ियों का कोई औचित्य नहीं। मनुष्य केवल मनुष्य है। जाति, वर्ण-भेद या धर्म के बंधन मिथ्या हैं, भ्रम हैं। इन बंधनों से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, मनुष्य उतना जल्दी मनुष्य बनेगा, राष्ट्र उतनी जल्दी विकास करेगा। किसी भी सभ्य समाज वाले देश में लोगों के बीच भिन्नता की जगह नहीं हो सकती। सोचने की जरूरत है कि अगर दो अलग वर्णों या जातियों के लोगों के अंग-प्रत्यंग एक ही संचरना में बंधे हैं तो वह शक्ति क्या हो सकती है जो इन्हें अलग करती है? सच यह है कि हमारा आदि और अंत एक है। हम चाहे समाज के जितने भी खंड कर लें, दुख होने पर आंसू और सुख होने पर हंसी, ये किसी विभाजन को नहीं देखते। हमारा अस्तित्व एक है और हमारा मनुष्य होना हमारा श्रेष्ठ परिचय है।

इसलिए मैं परिचय को इन सीमाओं में नहीं बांधती। धर्म, जाति या अन्य विशेषताएं मेरा परिचय नहीं। मैं अपना परिचय स्वयं मैं हूं। मेरा पूरा व्यक्तित्व मेरा परिचय है। विचार, बुद्धि, विवेक जैसी कई परिधियों से घिरा है यह परिचय। परिचय देने के लिए खुद से परिचित होना और आत्मबल होना जरूरी है। मेरुदंड की शक्ति परिचय है। लेकिन आज का युग इस परिचय का नहीं रहा। व्यक्ति तो है, पर व्यक्तित्व डूबता जा रहा है। 'रीढ़ की हड्डी' रोगग्रस्त हो गई है। बल क्षीण होता जा रहा है। फिर वास्तविक परिचय की जगह गहां! यथार्थ की वेदी पर कृत्रिम का झंडा लहरा रहा है। मनुष्य का अस्तित्व मनुष्य ही भूलता जा रहा है। पारलौकिक कल्पनाओं के अंधेरे में आस्था के परिचय से व्यक्ति का मनुष्य कराह रहा है। सब भाग रहे हैं... नाम, पद और परिचय के पीछे! नहीं... परिचय इस भागमभाग दौर की वस्तु ही नहीं!

संयम के साथ

पुलवामा के आतंकी हमले में 44 जवानों की शहादत के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आम आदमी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने का मतलब युद्ध करना या बम गिराना है जो आज के लोकतांत्रिक परिवेश में संभव नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अपने आदर्श, राजनीतिक संयम और मर्यादाएं भूल जाएं। सेना के जवानों की शहादत, घाटी के हालात और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को देख देश के लोगों का गुस्सा जायज है। ऐसे में आम आदमी का खून खौलना भी स्वाभाविक है। लेकिन एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जोश में होश न गंवाएं। सरकार और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सलाह न दें जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो। जैसे, पाकिस्तान को बम से उड़ा दो, उसे नेस्तनाबूद कर दो या घाटी के पत्थरबाजों को गोली मार दो! यह सच है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई का मतलब युद्ध ही नहीं होता है।

विपदा की घड़ी में राष्ट्र के हर नागरिक से संयम की उम्मीद की जाती है। कश्मीरी युवाओं के साथ मारपीट करना भी इसी असंयमशीलता का परिचायक है। बेशक जिस आतंकवादी मुल्क ने दहशतगर्दों को पनाह दी है, हमारे जांबाज सैनिकों की जान ली है उसे निशाना बनाया जाए लेकिन उसके लिए समूची कौम और समूचे कश्मीर को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं कहा जा सकता। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारी हर प्रतिक्रिया संयमित होनी चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आदर्श, मूल्य और परंपराएं इस तरह की भड़काऊ बातों की अनुमति नहीं देते। अगर हम भी वही सब करने लगे जो पाकिस्तान कर रहा है तो हममें और उसमें अंतर क्या रह जाएगा?

राजनीतिक दलों को चूंकि एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना होता है इसलिए सेना के मनोबल के नाम पर कुछ दिन साथ दिखने का दिखावा करने के बाद अब वे भले ही एक-दूसरे की आलोचना कर अपनी चुनावी पटरी पर लौट आए हों लेकिन एक नागरिक के नाते हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि किसी तरह की भड़काऊ बातें कर देश का वातावरण दूषित करें। आज के वैश्विक और प्रजातांत्रिक परिवेश में कूटनीतिक और आर्थिक युक्तियों से ही पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखा कर अलग-थलग किया जा सकता है। सेना का मनोबल गिराने वाली और भड़काऊ बातें करने से हर किसी को बचना चाहिए। जल्दी ही आम चुनाव है। नेताओं को भी चुनाव के दौरान ऐसे किसी वादे से जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए जिसे पूरा करना संभव न हो या जो बाद में किसी जुमले में तब्दील हो जाए!

● *देवेंद्र जोशी, महेश नगर, उज्जैन*

साजिश और संशय

बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड में नया मोड़ आ गया है। मोकामा भेजी गई लड़कियों में से सात के गायब होने की घटना संशय पैदा करने वाली है। आखिर ये लड़कियां क्यों भागी? ग्रिल काटने वाला हथियार कहां से आया? सात लड़कियों में से चार मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड गवाह हैं। इससे शक पैदा होता है कि कहीं यह एक बड़ी साजिश तो नहीं? ये लड़कियां खुद भागीं या इन्हें भगाया गया? हालांकि लड़कियां मिल गई हैं लेकिन इन सब बातों की जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

● *जफर अहमद, रामपुर डेहरू, बिहार*

बल्ले से जवाब

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद अब हर तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है जो कि जायज है। सरकार का भी इस मसले पर सख्त रुख देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को अनेक तरह से घेरे जाने की नीतियां बनाई जा रही हैं। इस मसले पर तमाम बुद्धिजीवी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों ने विश्व कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने का समर्थन किया है। हालांकि कुछ लोग उसके साथ क्रिकेट खेलने का समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मैच न खेलने से दुश्मन देश का ही फायदा होगा।

पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है लेकिन क्या महज क्रिकेट न खेलकर से उसे सबक सिखाया जा सकता है? विश्व कप का आयोजन आईसीसी द्वारा कराया जाता है और अगर भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी भारतीय टीम पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और उसे दो अंक मिलेंगे। इसलिए भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना चाहिए और पाकिस्तान को क्रिकेट की पिच पर बल्ले के साथ जवाब दिया जाना चाहिए। दुश्मन देश के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता लेकिन इसस अगर उसे थोड़ा भी फायदा होता है तो यह हमारे लिए अच्छा कैसे है?

● *सलीम जावेद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली*

महिला आइपीएल

आइपीएल को भारत में महज क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक त्योहार जैसा समझा जाता है। इस खेल में महिलाओं ने भी अपनी क्षमता और काबिलियत दर्शाई है। इसके मद्देनजर इस साल महिला आइपीएल का छोटा टूर्नामेंट कराने पर विचार किया जा रहा है। इसमें तीन टीमें खेल सकती हैं। पिछले साल आइपीएल के दौरान भी ऐसा ही किया गया था, जिसमें दो महिला आइपीएल टीमों के बीच मैच खेले गए थे। इसमें आइपीएल ट्रेलब्लेजर्स की कप्तानी पूर्व महिला कप्तान मिताली राज और आइपीएल सुपरनोवास की कप्तानी महिला टीम की वर्तमान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने की थी। महिला आइपीएल पूरी तरह से आयोजित न हो पाने का सबसे बड़ा कारण पैसों की तंगी और किसी भी टीम के लिए बोली लगाने वाले खरीदार न मिल पाना बताया जा रहा है। महिला क्रिकेट को मजबूती देने, साथ ही अधिक महिलाओं को क्रिकेट में बढ़ावा देने के लिए महिला आइपीएल का होना बेहद जरूरी है। बीसीसीआइ को इस पर ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि युवा लड़कियों को भी अपनी क्षमताएं दिखाने का मंच मिल सके।

● *निशांत रावत, दिल्ली विश्वविद्यालय*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com